साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 18-24 दिसंबर 2023 वर्ष-9, अंक-36

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

सावधान! इस साल भी कम होगी गेहूं की उपज

» सरकार को पहले से है गेहूं संकट का अंदेशा, पिछले दो साल में गेहूं पर मौसम की मार पड़ी

भोपाल। जागत गांव हमार

देशभर के अधिकतर राज्यों में गेहूं की बुवाई शुरू हो चुकी है। जिन राज्यों में बुवाई पिछड़ी हुई है, वहां भी जल्द ही इसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। गेहूं के उत्पादन के मामले में भारत शीर्ष पर है। कई देशों में भारत की तरफ से गेहूं निर्यात किया जाता है। हालांकि, पिछले कुछ साल से गेहूं की उपज जिस तरह की रही है, वह भारत के लिए चिंता का विषय है। पिछले दो साल में गेहूं की फसल पर मौसम की मार पड़ी है। साल 2023 के मार्च महीने में तापमान जून-जुलाई के बराबर पहुंच गया था। अचानक तापमान बढ़ने से गेहूं की फसल को ग्रोथ करने का मौका नहीं मिला। फसल समय से पहले पक गई। इससे गेहूं का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। वहीं, साल 2022 के सीजन में जब गेहूं पकने का समय आया तो बेमौसम बारिश की स्थिति का सामना करना पड़ा। इससे गेहूं के दानों पर काफी असर पड़ा और उसकी उपज प्रभावित हुई।

गेहूं के स्टॉक में आएगी कमी

केंद्र सरकार के मुताबिक, नवंबर महीने में गेहूं का बफर स्टॉक 210 लाख मीट्रिक टन है। कम होते स्टॉक के चलते गेहूं की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि, सरकार कीमत नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से गेहूं को ओपन मार्केट सेल के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए बफर स्टॉक का प्रयोग किया जना है। ऐसे में गेहूं का बफर स्टॉक और कम हो सकता है, जो चिंता का विषय है।

वादे बनेंगे गले की फांस

कई राज्य में राजनीतिक पार्टियों ने फ्री गेहूं और चावल देने की घोषणा की है। इस तरह के फैसले से भी गेहूं का बफर स्टॉक प्रभावित होगा। इसके चलते देश को गेहूं संकट का सामना करना पड़ सकता है और गेहूं इंपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है।

मोहन यादव सीएम, देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ

शिवराज विदा...अब मोहन राज

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। वे मप्र के 20वें मुख्यमंत्री हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ साढ़े नौ मिनट का रहा। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और दिग्गज मौजूद रहे।

नए मुखिया के शपथ ग्रहण में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने भले ही कोई भाषण नहीं दिया, पर उनके हाव-भाव में भी जन संदेश छुपा था। सीएम की शपथ लेने के बाद डॉ. मोहन यादव उनके पास पहुंचे तो मोदी ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए उनकी पीठ थपथपाई। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल से भी वह गर्मजोशी से मिले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुखी मन से कहा कि नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को शुभकामनाएं और मित्रों अब विदा।

सामने बैठे शिवराज

सफेद कुर्ता-पाजामा और काले रंग की जैकेट पहने मोदी मंच के बीचों-बीच बैठे। मोदी के दायीं और राज्यपाल और फिर नए मुख्यमंत्री मंचासीन थे। इनके दाहिनी ओर बड़ी संख्या में संत उपस्थित थे। संतों के लिए अलग मंच बनाया गया था। बायीं ओर सामने की पंक्ति में राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा उपस्थित थे।

मामा-मामा के नारे लगाए

प्रवेश के अन्य नेता पीछे की पंक्ति में थे। पीएम ने खुद मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों व राज्यपाल के साथ मंच पर फोटो खिंचवाया। प्रधानमंत्री जैसे ही मंच पर आए मोदी-मोदी के खूब नारे लगे। बीच में शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों ने मामा-मामा के नारे लगाए।

सात राज्यों के सीएम रहे शामिल

शपथ ग्रहण समारोह में सात राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, नगालैंड के सीएम नेफियू रियो, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद रहे।

» साढ़े नौ मिनट का समारोहः प्रधानमंत्री ने नए मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई

» पीएम डिप्टी सीएम देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला से भी गर्मजोशी से मिले

» पीएम मोदी बोले-डबल इंजन सरकार दोगुने जोश के साथ काम करेगी

» प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पांच लोगों के साथ मंच पर फोटो भी खिंचवाया

कैबिनेट का पहला फैसला | हर जिले में खुलेंगे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज

नए सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में काम संभाल लिया। उन्होंने पहला आदेश भी जारी कर दिया है। धार्मिक स्थलों तथा अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने का निर्देश दिया है। वहीं कैबिनेट की पहली बैठक की। जिसमें निर्णय लिया गया है कि हर जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। खुले में संचालित मांस या अंडे की दुकानों को बंद किया जाएगा। अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी होगा।

नर्मदापुरम जिले की छह सहकारी समितियों में खुलेंगे जन औषधि केंद्र

अब गांव में 50 से 90 फीसदी तक सस्ती मिलेगी दवाइयां

भोपाल। जागत गांव हमार

मप्र के जिलों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए भारत सरकार से अनुमति मिल गई है। ड्रग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद समितियों में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। शहरों के बाद अब गांवों में भी सस्ती जेनेरिक दवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके लिए नर्मदापुरम जिले की छह सहकारी समितियों में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इससे ग्रामीणों को 50 से 90 फीसदी तक सस्ती दवा मिलेगी। सहकारिता विभाग के जिला पंजीयक शिवम मिश्रा ने बताया की जिले में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए निर्धारित मापदंडों के साथ सांवलखेड़ा, इटारसी, सेमरीखुर्द, माखननगर, टाकसाला, समराखातर बनखेड़ी पैक्स से ऑनलाइन आवेदन किया है। जनता को सस्ती दर पर इलाज के लिए दवा उपलब्ध हो इसके लिए केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत में जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लेते हुए पैक्स से समय पर ऑनलाइन आवेदन किया है। इसके लिए विभाग ने सभी पैक्स को पत्र जारी कर दिया है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पैक्स के सशक्तिकरण के साथ कम्प्यूटरीकृत किया जाना है।

1.24 लाख पंचायतों का चयन| दरअसल, केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब गांवों में ही सस्ती दवाएं मिलेंगी। केंद्र ने 2000 हजार पैक्स में पीएम भारतीय जन औषधी केंद्र बनाने का फैसला लिया है। वहीं केंद्र ने 1.24 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की पहचान की है, जिसमें या तो कोई पैक्स या डेयरी सहकारी या दोनों ही नहीं है। देश में 2,69,364 ग्राम पंचायतों में से 96,405 पंचायतें ऐसी हैं, जहां न तो कोई पैक्स हैं और न ही कोई डेयरी सहकारी समितियां हैं, अब सहकारिता मंत्रालय ने एक डेटाबेस बनाने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त , 27,954 पंचायतें हैं।

उच्च गुणवत्ता की मिलेंगी दवाएं

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र परियोजनाएं अंतर्गत लगभग 1,900 प्रकार की उच्च गुणवत्ता की दवाएं एवं 285 शल्य चिकित्सा उपकरण एवं विभिन्न प्रकार के पाउडर भी उपलब्ध रहेंगे। इसमें प्रोटीन पाउडर, माल्टा बेस्ट फूड सप्लीमेंट इत्यादि सहित अन्य प्रकार की विटामिन की दवा भी उपलब्ध रहेगी। आयुष की 64 प्रकार की आयुर्वेदिक दवा भी उपलब्ध रहेगी। इसमें विटामिन की दवा एवं च्यवनप्राश भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में शामिल किया गया है। जन औषधि केंद्र में संचालक को 5 लाख तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

अपने हुनर से लॉन्ड्री बास्केट, टोकरियो, प्लेटें, कटोरे, चाय कोस्टर, कैरी बैग और फुट मैट तैयार कर रहीं

जलकुंभी से संवर रही जिंदगी

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार-पश्चिम बंगाल जैसे छह राज्यों की तीन हजार महिलाओं को मिला घर बैठे रोजगार

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत सरकार ने गंगा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवित करने के अपने एक प्रोजेक्ट में ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया है। इस पहल की बदौलत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे छह राज्यों में 3,000 से ज्यादा महिलाएं न केवल गंगा को बचाने के काम में मदद कर रहीं हैं, बल्कि उसे अपने लिए रोजगार का एक जरिया भी बना लिया है। भारत में जल निकायों में आमतौर पर मिलने वाले जलीय खरपतवार जलकुंभी को वह अपने हुनर के जरिए लॉन्ड्री बास्केट, टोकरियो, प्लेटें, कटोरे, चाय कोस्टर, कैरी बैग और फुट मैट जैसे उपयोगी उत्पाद तैयार कर रही हैं। इनकी बिक्री से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है।

इको-प्रोडक्ट्स बनाने ली ट्रेनिंग- झारखंड की शीलन देवी महिलाओं के उस समूह का हिस्सा हैं जो केंद्र सरकार की जलज परियोजना के साथ जुड़ी हुई हैं। इस परियोजना का मकसद गंगा और नदी के बेसिन में रहने वाले लोगों के बीच सहजीवी संबंध बनाना है। आजीविका के अवसरों को जलीय प्रजातियों के संरक्षण के साथ जोड़ना है। साहिबगंज जिले के मस्कलैया गांव में रहने वाली 40 वर्षीय शीलन देवी पिछले एक साल से अपने गांव और उसके आसपास के नदी तालाबों से जलकुंभी इकट्ठा कर, उनसे तरह-तरह के चीजें तैयार करती हैं। उन्होंने इन इको-प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग ली है।

जलकुंभी निकालना मुश्किल काम

महिलाओं ने बताया कि तालाब से जलकुंभी निकालना एक मुश्किल काम है, क्योंकि खरपतवार का निचला हिस्सा जड़ों में गहराई से जुड़ा होता है। इसे दरांती से बड़ी ही मुश्किल से निकाल पाते हैं। उसके बाद इस खरपतवार को धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है और फिर मैं इससे चीजें बनाती हूं। जलकुंभी की सूखी टहनियों से लॉन्ड्री बास्केट, प्लेटें, कटोरियां आदि बनाया जाता है।

26 गांवों में शुरू की गई पहल

जल शक्ति मंत्रालय ने पिछले अगस्त गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए एक पहल जलज शुरू की थी। स्थानीय लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई और फिर उन्हें अपने साथ जोड़ा लिया गया। यह पहल उत्तर प्रदेश (11 केंद्र), पश्चिम बंगाल (छह केंद्र), बिहार (पांच केंद्र), उत्तराखंड (दो केंद्र), झारखंड (एक केंद्र) और मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों में गंगा, यमुना, गोमती, हुगली और चंबल नदियों के किनारे बसे 26 गांवों में शुरू की गई है।

केंद्र सरकार कर रही मदद

देहरादून स्थित वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह संस्थान स्थानीय समुदायों के साथ काम करके परियोजना के कार्यान्वयन में भारत सरकार की मदद कर रहा है। जलज परियोजना में महिलाओं को जलकुंभी से उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए जलज उत्सवी महिला समूह केंद्र खोले गए हैं। झारखंड की शीलन देवी एक ऐसी ही महिला समूह का हिस्सा हैं।

नदी को कर रहीं जिंदा

दरअसल, ये गंगा प्रहरी वालियंटर होते हैं, जो स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर जैव विविधता संरक्षण और नदी को फिर से जिंदा करने का काम करते हैं। जलज उत्सवी महिला समूह केंद्र ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देता हैं और कार्यशालाएं आयोजित करता है। इन केंद्रों पर महिलाएं पहले गंगा प्रहरियों से चीजें बनाना सीखती हैं और फिर अपने गांव में खरपतवार इकट्ठा करके उनसे चीजें तैयार करती हैं। फिलहाल इस परियोजना के तहत कुल 26 ऐसे केंद्र बनाए हैं और उनमें से एक झारखंड में है। इस केंद्र से लगभग 150 महिलाएं जुड़ी हैं।

लाभ का धंधा: 5500 रुपए किलो बिक रहा दूध

पशु पालकों के लिए मुनाफे का सौदा पहाड़ी गाय 'बद्री'

आम गाय के घी से 5 गुना ज्यादा घी के दाम

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत में पशुपालन के प्रति बढ़ती रुचि यहां की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। इधर, पशुपालकों के साथ-साथ आम जनता भी पशुपालन की ओर रुख करती नजर आ रही है। आज के समय में लोग अधिक कमाई के लिए एक साथ कई काम करते हैं। भारत में गाय पालने का चलन बढ़ता जा रहा है। चाहे खेती की लागत कम करना हो या दूध बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करना हो। इन सभी कार्यों में गाय बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। देसी गाय का दूध और घी भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो सभी देशी नस्ल की गायों की अपनी एक खास बात होती है, लेकिन आज हम उस देशी गाय के बारे में बात करेंगे, जिसे पहाड़ों की कामधेनु के रूप में दर्ज किया गया है। इस गाय के दूध में सामान्य गाय के दूध से ज्यादा पोषण होता है। इसीलिए इस गाय के दूध से बना घी बाजार में 5,500 रुपए प्रति किलो के दाम पर बिक रहा है। हम बात कर रहे हैं बद्री गाय की, जिन्हें छोटे किसानों का मसीहा भी कहा जाता है।

कितना दूध देती है बद्री गाय

बद्री गाय की एक देशी नस्ल है, जो उत्तराखंड में पाई जाती है। अन्य गायों की तुलना में बद्री गाय 3 से 4 लीटर ही दूध देती है, लेकिन इसके दूध से बना घी 5,500 रुपये प्रति किलो यानी आम गाय के घी से 5 गुना ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। इस गाय से दूध का उत्पादन कम होता है इसलिए अब लोग इसे पालना पसंद नहीं करते। डेयरी के व्यावसायीकरण के बाद बद्री गाय विलुप्त होती जा रही है, लेकिन कई डेयरी फार्मों ने बद्री गाय के दूध की मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता को समझा है और इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं।

इसलिए इतना महंगा घी

बद्री गाय को पहाड़ी या ठंडे इलाकों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। कई शोधों से यह बात साबित हो चुकी है कि बद्री गाय के दूध में बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती है। इसके दूध में 8.4 प्रतिशत वसा होती है, जो किसी भी गाय या भैंस के दूध से कहीं अधिक है।

प्रोटीन से भरपूर दूध

बद्री गाय के दूध में कुल ठोस पदार्थ 9.02 प्रतिशत तथा कच्चा प्रोटीन 3.26 प्रतिशत होता है। बद्री गाय का दूध न केवल ए-2 प्रोटीन से भरपूर होता है, बल्कि इसमें कई सरल पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इसीलिए दूध से लेकर छाछ, मक्खन और घी तक लगभग सभी दुग्ध उत्पाद महंगे हैं।

उड़नदस्ता दल ने 77 क्विंटल धान मौके से की जब्त

कटनी में 200 बोरी धान के साथ व्यापारी हुआ गिरफ्तार

कटनी। जागत गांव हमार

नेशनल हाईवे किनारे बने कैलवाराकलां खरीदी केंद्र में क्षेत्र के व्यापारी द्वारा बाहर से कम दामों में धान खरीद कर उसे उपार्जन केन्द्र में खपाने की नियत से पहुंचा था। तभी कृषि उपज मंडी का उड़नदस्ता अचानक पहुंचकर मिनी ट्रक पर शिकंजा कसते हुए उसमें लोड 200 बोरियों में करीब 77 क्विंटल धान की जब्ती बनाई है। कार्रवाई में शामिल रहे एसडीएम राकेश चौरसिया ने बताया की मंडी सचिव राकेश पनिका अपने उड़नदस्ता दल के साथ खरीदी केंद्र में दबिश देते हुए सियाराम एंड संस गाड़ी क्रमांक एमपी 21 जी 1045 में 10 लाख कीमती 76.80 क्विंटल धान जो करीब 200 बोरियों में बंद मिला, उसकी जब्ती 8 लाख कीमत की गाड़ी के साथ किया है।

4 के खिलाफ मामला दर्ज

पूरे मामले पर जिला प्रशासन की ओर से कृषि उपज मंडी के सचिव राकेश पनिका ने 4 लोगों के खिलाफ कुठला थाने पहुंचकर आरोपी जुगल किशोर प्यासी, इंद्रभान पटेल, श्रीचंद्र यादव सहित गाड़ी चालक मोनू पर धारा 420, 34, 511 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। पिछले कुछ वर्षों से व्यापारियों द्वारा यूपी और छत्तीसगढ़ से कम दामों में धान लाकर जिलेभर में पलटी करते हुए शासन से मोटी रकम कमाते थे। जिस पर लगाम लगाने के लिए कलेक्टर अवि प्रसाद ने संयुक्त नाकों पर उड़नदस्ता दल गठित कर बाहर से आ रहे धान, गेहूं, बटरी सहित अन्य उपज पर निगरानी के निर्देश दिए हैं।

मत्स्य समृद्धि योजना अन्तर्गत रीवा में 2.85 लाख मत्स्य बीज का हुआ संचयन

रीवा। गोविंदगढ़ जलाशय में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरों के हित में मत्स्य समृद्धि योजनान्तर्गत 2.85 लाख मत्स्यबीज का संचयन किया गया। सहायक संचालक मत्स्य डॉ. अंजना सिंह ने बताया कि यह संचयन विभागीय तालाबों में कार्यरत मछुआ समिति के सदस्यों के जीवन यापन एवं रोजगार के लिए शासन द्वारा संचालित है। मछुआरों को हिदायत दी गई कि छोटे साईज के फंदे के जाल जलाशय में न लगाएं, सिर्फ बड़ी मछलियां का ही मत्स्याखेट करें। इस योजना का उद्देश्य मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों के जीवन यापन एवं तालाब की जैव विविधता बरकरार रखना है। उल्लेखनीय है कि नदी/ जलाशय मत्स्य समृद्धि योजनान्तर्गत विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष मत्स्य बीज संचयन कराया जाता है। संचयन कार्यक्रम में मछुआ समिति के अध्यक्ष, नगर पंचायत गोविंदगढ़ के उपाध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोविंदगढ़ तथा सुरंजन सिंह एवं अन्य स्थानीय नागरिक उपस्थित थे ।

-रूफटॉप सोलर नेट मीटर को लेकर रूचि बढ़ी, अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी पहल

इंदौर में सूरज की किरणों से 10650 स्थानों पर तैयार हो रही बिजली

इंदौर। जागत गांव हमार

सूरज की किरणों को अपने मकान, दुकान, कार्यालय, कारखाने व अन्य परिसर पर सोलर पैनल्स लगाकर बिजली तैयार करने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। अब मालवा व निमाड़ में कुल 10650 स्थानों पर रूफटाप सोलर नेट मीटर योजना के तहत सेटअप लगाकर बिजली तैयार हो रही है। उपभोक्ता प्रतिमाह चार से साढ़े चार करोड़ रुपए बाजार कीमत की बिजली तैयार कर रहे हैं। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अभिनव पहल है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि रूफटॉप सोलर नेट मीटर केंद्र व राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है। इस पर कंपनी हर संभव पहल कर इच्छुक बिजली उपभोक्ताओं के अपने परिसरों पर सोलर पैनल्स लगाने के आवेदनों का तेजी से निराकरण कर मंजूरी देती है। पिछले छह माह में ही कंपनी स्तर पर पौने दो हजार प्रकरणों की मंजूरी दी गई है।

नियमित रूप से समीक्षा

तोमर ने बताया कि कंपनी क्षेत्र के सभी 55 कार्यपालन यंत्रियों को रूफटॉप सोलर नेट मीटर प्रकरण मंजूरी के अधिकार है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा भी होती है। तोमर ने बताया कि कोयले एवं पानी से बिजली बनाने की बजाए सूरज की किरणों से बिजली तैयार करना पर्यावरण के लिए अत्यंत हितकर पहल है, इस दिशा में कंपनी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की रूचि एवं समर्पण सराहनीय है।

उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बढ़ रही संख्या

तोमर ने बताया कि वर्तमान में इंदौर शहर, सुपर कॉरिडोर, बायपास पर कुल 6300 स्थानों पर सूरज की किरणों से बिजली तैयार हो रही है। इसी तरह उज्जैन जिले में 1310 स्थानों पर, रतलाम जिले में 450 स्थानों पर, खरगोन जिले में 360 स्थानों पर, नीमच जिले में 280 स्थानों पर, देवास जिले में 260 स्थानों पर, मंदसौर जिले में 205 स्थानों पर सूरज की किरणों से बिजली तैयार हो रही हैं। अन्य जिलों में भी 25 से 150 स्थानों पर सौर ऊर्जा से बिजली मिल रही है।

थकान होगी दूर और महिलाएं बच्चों की पढ़ाई पर दे सकेंगी ध्यान

देश के छह लाख गांवों की बदल रही तस्वीर पर हर घर नल जल की दरकार

-सुरक्षित पीने योग्य पानी की सप्लाई पर सरकार का जोर

भोपाल। जागत गांव हमार

देश के छह लाख से ज्यादा गांवों की तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है। कभी बिजली का होना जहां बड़े सपने के सच होने जैसा था वहां अब सुबह शाम दोनों समय बल्ब जलते हैं। लेकिन पानी की किल्लत पूरी तरह अब तक दूर नहीं हुई है। कई राज्यों में अभी भी पीने का पानी लाने के लिए दूर के हैंडपंप या तालाब, नदी तक गांव की महिलाओं को लम्बा सफर तय करना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अगर देश के सभी गांवों के हर घर में नल लग जाए तो इससे 5.5 करोड़ घंटे से अधिक समय की बचत होगी। ये वो समय है जो महिलाएं पानी की जरूरत को पूरा करने में खर्च कर देती हैं। साफ है, गांव की महिलाओं के पास खुद के लिए जब अधिक समय होगा तो न सिर्फ उन्हें रोजाना के थकान से कुछ राहत मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे सकेंगी।

जल्द ही हर घर में नल होगा- केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर के मुताबिक सरकार देश के सभी गांव के परिवारों को नल के कनेक्शन से सुरक्षित पीने योग्य पानी की सप्लाई के लिए तेजी से काम कर रही है। उम्मीद है जल्द ही हर घर में नल की सुविधा होगी। सभी राज्यों के साथ केंद्र सरकार मिलकर इस मिशन को पूरा करने में जुटी है। काफी हद तक काम पूरा कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों के साथ साझेदारी में लागू होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की थी। पीने के पानी से जुड़ा काम राज्य सरकार देखती है।

देश में हर घर नल से महिलाओं के बचेंगे 5 करोड़ घंटे

गांवों में तेजी से काम हुआ

जल जीवन मिशन के तहत पानी की सप्लाई सहित, योजना को सही तरीके से लागू करने और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की ही है। भारत सरकार इस संबंध में तकनीकी और आर्थिक रूप से राज्यों का सहयोग करती है। सरकार का कहना है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से देश के गांवों के घरों तक नल से पानी की पहुंच बढ़ाने में तेजी से काम हुआ है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में सिर्फ 3.23 करोड़ (16.8 प्रतिशत) गांव के घरों में ही नल से पानी के कनेक्शन होने की जानकारी थी।

10.53 करोड़ नल कनेक्शन

अब तक, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तरफ से 7 दिसंबर 2023 को दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 10.53 करोड़ अलग से गांव के परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से पानी का कनेक्शन दिया गया। देश के 19.24 करोड़ गांव के परिवारों में से करीब 13.76 करोड़ (71.51 प्रतिशत) परिवारों के घरों में नल से पानी की सप्लाई होने की जानकारी दी गई है। गांव के समुदायों और पंचायतों के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए जल आपूर्ति प्रणालियों से संबंधित सभी फैसलों में गाँव स्तरीय योजना और सामुदायिक भागीदारी के सभी पहलुओं को इस योजना में शामिल किया गया है।

50 प्रतिशत महिला सदस्य

राजीव चन्द्रशेखर के मुताबिक महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मिशन के तहत जोर दिया जाता है। यही वजह है कि पंचायतों की 5.29 लाख से अधिक उप-समिति,उपयोगकर्ता समूह यानी ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) या पानी समिति, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत महिला सदस्य हैं, उनके सहयोग से समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए ये प्रतिनिधित्व का गठन किया गया है। राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय जल राज्य मंत्री ने कहा कि इन सभी को गांव में पानी की सप्लाई की योजना बनाने उसे लागू करने और रखरखाव के लिए समूह में रखा गया है।

महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

फील्ड टेस्ट किट के जरिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए हर गांव से पांच महिलाओं को चुना जाता है। फिर उन्हें इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक 23.36 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। साल 2023-24 में फील्ड टेस्ट किट के जरिए अब तक 82.05 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। 14,000 से अधिक गैर सरकारी संगठन, वीओ, महिला स्वयं सहायता समूहों, सीबीओ, और ट्रस्ट फाउंडेशन जिन्हें आईएसए कहा जाता है, उनको गांव में पानी सप्लाई, सहयोग, प्रबंधन और रखरखाव के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए देश भर में लगाया गया है।

चम्बल फर्टिलाइजर्स के सहकारिता से समृद्धि विषय पर बनाया गया लघु चलचित्र मिला पुरस्कार

नई दिल्ली। उर्वरक एवं कृषि क्षेत्र में नवाचार विषय पर एफएआई द्वारा कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर संस्थान द्वारा नवाचार को बेहतर करने के लिए बनाये लघु चल चित्रों को पुरस्कार प्रदान किये गए। इसी क्रम में चम्बल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स द्वारा सहकारिता से समृद्धि विषय पर बनाया गया लघु चलचित्र ने श्रेष्ठ द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार कम्पनी के जितेन्द्र सकलानी को उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा प्रदान किया गया। इस लघु चलचित्र के माध्यम से ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के विभिन्न आयामों में सहकारिता के माध्यम से हो रही समृद्धि को क्रमबद्ध रूप से दर्शाया गया है। दिखाये गये प्रेरणादायक कार्य उनकी संचालन विषयों से प्राप्त समृद्धि सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। यह चलचित्र अन्य उत्साही ग्रामीण एवं कृषकों के जीवन में समृद्धि लाने में एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोगी होगा। चम्बल फर्टिलाइजर्स ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए कृषि आदानों के वितरण, शिक्षण एवं नव विचारों के द्वारा अपना योगदान दे रही है।

मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवॉर्ड 2023 में बैतूल के किसान को लखपति कृषक का पुरष्कार

बैतूल। कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल के अंगीकृत गांव के कृषक जयराम गायकवाड़ को जिले के लखपति कृषक का खिताब प्राप्त हुआ। कृषक की खिताब हेतु दावेदारी के लिए केन्द्र द्वारा कृषक का समुचित आर्थिक विवरण प्रस्तुत किया गया। तदोपरांत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा, नई दिल्ली द्वारा महिन्द्रा ट्रेक्टर के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 में कृषक जयराम गायकवाड़ को जिला बैतूल के लखपति कृषक के रूप में सम्मानित किया।

पीएम मोदी की भारत संकल्प यात्रा से किसानों को फायदे ही फायदे

विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों व पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना और नई योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाना है। इसका प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी से शुभारंभ किया था। सरकार को इस यात्रा के तहत आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) वैन के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्र एंव ग्राम पंचायतों तक पहुंच बनाना हैं। मोदी के विकास की गारंटी वाली गाड़ी देश के हर गांव, तहसील, ब्लॉक, एंव जिलों में जाकर किसानों व हितग्राही लोगों को केंद्र व राज्य की योजनाओं के बारे में जागरूक करेगी।

भारत संकल्प यात्रा उन किसानों को जो केंद्र व राज्य की योजनाओं से अभी तक वंचित हैं उनको इन योजनाओं से जोड़ेगी और सरकार की सभी सुविधांए उपलब्ध करायेगी।

योजनाओ की जानकारी: इस यात्रा से किसानों को केंद्र व राज्य की सभी कृषि योजनाओं व सेवाओं से अवगत कराया जा रहा हैं और वंचित लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं जैसे फसल बीमा योजना, पीएम किसान योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, ड्रोन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-नाम, प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन योजना, पीएम प्रणाम, नैनो उर्वरक योजना और राष्ट्रीय बागवानी मिशन आदि किसानों के लिए बेहद जरूरी हैं। हालांकि, किसानों को अपनी खेती किसानी के कार्यों के लिए कृषि योजनाओं की तो जरूरत होती हैं। इसके अलावा भी किसानों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र की अन्य योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना, हर-घर जल योजना, जनधन योजना, पीएम ज्योति बीमा योजना एंव पीएम ग्रामीण आवास आदि योजनाओं की भी काफी जरूरत होती हैं।

योजनाओं में कैसे हो सकते है शामिल: केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रहीं कृषि योजनाएं खेती-किसानी से लेकर व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए लोन से लेकर सब्सिडी, इंसेंटिव, फसल बीमा का लाभ देती हैं। लेकिन कुछ किसान अभी भी सरकार की इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहें हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान अपने गांव, शहर या कस्बे में आने वाली भारत संकल्प यात्रा की वैन से संपर्क करें या इस यात्रा के जगह-जगह सिविर लगे हुए हैं। किसान इन सिविरों में जाकर भी अपनी सभी खेती-किसानी एंव कृषि योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकतें हैं। यह यात्रा भारत सरकार, राज्य सरकारों व केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एंव विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ चलाई जा रही है। इस यात्रा द्वारा किसानों की कृषि एंव व्यक्तिगत समस्याओं का निदान किया जायेगा। इसके अलावा किसानों को राज्य व केंद्र की योजना से जोड़ने में मदद की जायेगी।

समस्या समाधान: सरकार की कृषि व व्यक्तिगत योजनाओं से जो किसान पहले से अवगत हैं और वह इन योजना से जुड़े हुए भी हैं लेकिन तब भी किसी कारण से वह उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहें हैं। तो ऐसे किसान भी अपनी समस्या के समाधान के लिए भारत संकल्प यात्रा का सहारा ले सकते हैं। यह यात्रा आपको निश्चित रूप से आपकी समस्या का हल सुनिश्चित करेगी और केंद्र व राज्य की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने में मदद करेगी।

नई योजनाओं की जानकारी: सरकार ने वर्ष 2023 में एक बहुत महत्वकांक्षी योजना को कृषि क्षेत्र के अंदर शुरू किया हैं। सरकार ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदार बढ़ाने के लिए ड्रोन दीदी योजना की शुरूआत की हैं। सरकार इस योजना से महिला किसानों को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भर बनाने एंव रोजगार सृजन से महिला किसानों की आजीविका में सुधार करना चाहती हैं।

इसके अलावा सरकार काफी समय से किसानों के हितों के लिए विभिन्न सारी योजनाएं चला रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो इन से जुड़े ही नही हैं, कुछ जुड़े हैं लेकिन वह इन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और कुछ किसानों को तो अभी तक सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ही नहीं हैं। तो ऐसे किसानों के लिए सरकार ने समय-समय पर उन सभी योजनाओं से अवगत कराने के लिए कोशिश की लेकिन इन सबके बाद भी किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग इन योजनाओं से वंचित हैं। इसलिए सरकार अब विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा किसानों के गांव, शहरों व कस्बों में उनके पास जाकर उनकों सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देगी और लाभ उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। भारत संकल्प यात्रा सरकार की एक तरह से घर-घर अभियान की तरह हैं, जो किसानों को जागरूक करने का कार्य कर रही हैं।

उड़द की उन्नत कास्त विधि

डॉ. सविता आदित्य
डॉ. बी. एस. राजपूत
श्री के.के. पैंकरा
डॉ. एन. सी. बंजारा
कृषि विज्ञान केन्द्र,
रायगढ़, छग

उड़द एक दलहनी फसल है, इसका उपयोग मुख्य रूप से दाल तथा दाल को पीसकर पापड़, बड़ियां, लड्डू आदि व्यजंनों के रूप में किया जाता है। फास्फोरस अम्ल की पर्याप्त मात्रा होने के कारण इसका दैनिक आहार में बहुत महत्व है। उड़द का हरा तथा सूखा हुआ पौधा पषुओं के लिए एक स्वादिष्ट एवं पौष्टिक चारा के रूप मे प्रयोग किया जाता है। उड़द की खेती करने से उडद के बाद लगाने वाली फसल की उपज में 15 से 20 प्रतिषत तक बढ़ोत्तरी होती है तथा भूमि की उर्वरा षक्ति भी बनी रहती है।

उड़द की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है लेकिन उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि उड़द की खेती के लिए सर्वोत्तम सिद्ध हुई है।

उन्नतशील प्रजातियां: आर. बी. यू-38 (बरखा), टी.यू. 94-2, टी.पी.यू.-4, टी.पी.यू.-2, इंदिरा उड़द प्रथम आदि।

बीज की मात्रा: खरीफ में बोई जाने वाली फसल के लिए 15-20 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बसंतकालीन फसल के लिए 25-30 किलो बीज प्रति है. की दर से जरूरत होती है।

बुवाई का समय: बसंतकालीन फसल के लिए फरवरी के दूसरे एवं मार्च के प्रथम पखवाड़े में बुवाई करनी चाहिए। खरीफ की फसल की बुवाई जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक कर देनी चाहिए। उड़द की कम अवधि की प्रजातियों को खरीफ में देर से (अगस्त व सितम्बर के पहले सप्ताह में) बुवाई करके उड़द की अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। देर से बीजाई करने पर उत्पादन में काफी कमी आ जाती है। बसंतकालीन फसल को 20-25 सेमी की दूरी पर बनी पंक्तियों में तथा खरीफ की फसल की बुवाई 30-45 सेमी की दूरी पर कतारों में बोया जाना चाहिए एवं पौधें से पौधे की दूरी 8-10 सेमी रखनी चाहिए। उड़द की बुवाई 5-6 सेमी की गहराई पर डालना चाहिए।

एफ.आई.आर. विधी द्धारा बीजोपचार: फफूंदनाशक, कीटनाशक एवं रायजोबीयम कल्चर एफ.आई.आर द्धारा बीजोपचार, जिसमें बीजों को फफूंदजनित रोगों जैसे उकठा, जड़ गलन एवं तना गलन से बचाव के लिए सबसे पहले फफूंदनाषक जैसे कार्बेन्डाजिम का 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार, उसके बाद रस चूसक कीट के लिए जो कि पीला मोजेक वायरस का प्रमुख वाहक होता है जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती है जिसके बचाव हेतु अंतरवाही कीटनाशक जैसे थायोमिथोक्सास 75 डब्लू. जी. का 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार एवं अंत में जीवाणु कल्चर जैसे रायजोबियम का 5-10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करने से फसल की नाईट्रोजन की आवश्यकता पूरी होती है बल्कि अगली फसल के लिए नाईट्रोजन की आवश्यकता कम हो जाती हैं। फफूंदनाशक, कीटनाशक एवं रायजोबीयम कल्चर के क्रम से उपचारित कर, उचित बीज दर द्वारा, सही समय, पर्याप्त गहराई तथा उचित दूरी पर बोवाई कर अधिक उत्पादन ले सकते हैं।

खाद एवं उर्वरक: उड़द एक दलहनी फसल है, जिसमें नाइट्रोजन उर्वरकों को आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कमजोर भूमि में 20-25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हैक्टेयर की दर से डालना ठीक रहता है। ऐसी भूमि जिसमें फास्फोरस की कमी है प्रति हैक्टेयर 40-50 किग्रा. फास्फेट उर्वरक डालना जरूरी है तथा पोटाश की कमी होने पर 15-20 किलो पोटाश डालना चाहिए।

निराई गुड़ाई: बुवाई के बाद तीसरे या चैथे सप्ताह में पहली निराई गुड़ाई तथा आवश्यकतानुसार दूसरी निराई बुवाई के 40-50 दिन बाद करनी चाहिए। घास तथा चैड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को रासयनिक विधि से भी नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए फ्लूक्लोरोलिन (45 ई.सी.) की 2 लीटर मात्रा प्रति हैक्टेयर की दर से आवश्यक पानी मे मिलाकर बुवाई के पहले भूमि पर छिड़काव करके मिट्टी में मिला दें अथवा पेन्डिमिथालिन (30 ई.सी.) 3.3 लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से 800-1000 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के तुरन्त बाद जमाव से पूर्व छिड़काव करें।

सिंचाई: बसंतकालीन फसल में 10-15 दिन के अंतर पर सिंचाई करना आवश्यक होता है, पहली सिंचाई बुवाई के 20-25 दिन बाद करनी चाहिए। खरीफ मौसम की फसल को बहुधा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

जल निकास: उड़द की फसल में वर्षा के कारण पानी भर जाये तो पानी को निकाल देना चाहिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उड़द को मेड़ों पर बोना चाहिए ताकि मेड़ों के द्वारा बनी नालियों द्वारा उचित जल निकास हो सके जिससे भूमि में वायु का उचित संचार भी हो सके।

प्रमुख कीट एवं समन्वित प्रबंधन: (अ) फली भेदक कीट, 1. फलीभेदक (हेलियोथिस आर्मीजेरा)

पहचान: इस कीट के अंडे चमकीले हरे रंग के होते है। इल्लियों के रंग में विविधता पाई जाती है जो कि हरे गुलाबी, पीले, काले एवं भूरे रंग की होती है तथा षरीर पर हल्की एवं गहरी धारियाँ पाई जाती है। प्रौढ़ कीट भूरे रंग का तथा आगे की पंखो में सेम के बीज के समान एक-एक काला धब्बा व पीछले पंख के बाहरी किनारों पर काली पट्टी दिखाई देती है। इस कीट की छोटी इल्लीयाँ पौधों की कोमल पत्तियों एवं विकसीत फली को खुरचकर खाती है। अर्धविकसित इल्लियाँ फली के उभरे भाग में छेद करके विकसीत हो रहे दानों में अपना सिर घुसाकर एवं षरीर का षेष भाग बाहर रखकर खाती रहती हैं। एक इल्ली करीब 30-40 फल्लीयों को नुकसान पहुँचाती है।

कीट सक्रियता: दैनिक न्यूनतम तापमान 10 से 14 से.ग्रे., 75 प्रतिषत आर्द्रता एवं बादलयुक्त मौसम कीटों की सक्रियता के लिए अनुकूल होता है।

अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवसः 30 मई को मनाया जाएगा अनोखा उत्सव

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाने के संयुक्त राष्ट्र के फैसले को मंजूरी दे दी हैं। आलू अरबों लोगों द्वारा नियमित रूप से उपभोग की जाने वाली सब्जी हैं। इसलिए इसकी फसल के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर हैं।

पेरू ने 7 जुलाई, 2023 के एफएओ सम्मेलन के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 2008 में मनाए गए आलू के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पर आधारित इस दिवस के लिए प्रोत्साहन, खाद्य असुरक्षा, गरीबी और पर्यावरणीय खतरों जैसे प्रचलित वैश्विक मुद्दों से निपटने में आलू की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने की आवश्यकता से उत्पन्न होता है।

एफएओ के उप महानिदेशक बेथ बेचडोल ने कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस आलू के महत्वपूर्ण मूल्य जैसे पोषण, आर्थिक, पर्यावरण पर प्रकाश डालेगा। यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा, गरीबी में कमी और लाखों लोगों की आजीविका में आलू के योगदान को भी उजागर करेगा, जबकि स्वदेशी लोगों के ज्ञान और प्रथाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देगा।

संयुक्त राष्ट्र में पेरू के स्थायी प्रतिनिधि विक्टर गार्सिया टोमा ने महासभा को बताया, यह दिन हमें भूख, कुपोषण और गरीबी को कम करने के प्रयासों को बनाए रखने में इस पैतृक फसल के महत्व पर ध्यान आकर्षित करने की अनुमति देगा। इसके साथ ही कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

एक फसल, बहुत अधिक क्षमता: आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिकी एंडीज क्षेत्र में हुई थी। जो 16वीं शताब्दी में यूरोप में उपभोग के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर इसके बाद आलू पूरी दुनिया में उपभोग के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा।

प्राकृतिक संसाधन, विशेष रूप से कृषि योग्य भूमि और सीमित पानी और महंगे कृषि आदान की स्थिति में आलू ग्रामीण और अन्य शहरी क्षेत्रों में भी सुलभ और पौष्टिक भोजन और बेहतर आजीविका का एक महत्वपूर्ण घटक है। फसल की बहुमुखी प्रतिभा और विभिन्न परिस्थितियों में बढ़ने की क्षमता इसे एक लाभप्रद फसल का विकल्प बनाती है।

पिछले एक दशक में, आलू के वैश्विक उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे रोजगार और आय में वृद्धि हुई है, लेकिन विश्व स्तर पर भूख और कुपोषण को समाप्त करने में फसल की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए अभी भी और काम करने की आवश्यकता है।

» हर साल 400 करोड़ रुपए का किसान कर रहे कारोबार

» पूरे जिले में करीब 40 हजार हेक्टेयर में मटर का उत्पादन

जबलपुर की मटर की विदेश में भी डिमांड, मिल चुका जीआई टैग

जबलपुर। जबलपुर की मटर दुनिया भर में मशहूर है। भरा हुआ दाना और लाजवाब स्वाद। इतनी बढ़िया मटर की फोजन करने के बाद भी उसका स्वाद नहीं बदलता। मटर का दाना कितने भी दिन बाद खाया जाए वो हमेशा उतना ही तरोताजा बना रहता है जैसे अभी खरीद कर लाए हों। जबलपुर अपने हरे भरे मटर के लिए प्रसिद्ध है। यहां की मिट्टी में पैदा हुआ मटर विदेश में भी शान से इठलाता है। पूरे जिले में करीब 40 हजार हेक्टेयर में मटर का उत्पादन होता है। ये यहां की प्रमुख सीजनल फसल है। जबलपुर का मटर देश के कई राज्यों में भेजा जाता है। इसके अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी इस मटर को काफी पसंद किया जाता है। यही वजह है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत यहां के मटर को जबलपुर की पहचान और प्रमुख उत्पाद के रूप में टैग दिया गया है। जिले के किसान प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रुपए का मटर बेचते हैं।

दुनिया भर में मशहूर जबलपुरी मटर भले ही खूब शोहरत पा रहा है, लेकिन इस मटर के उत्पादक किसान आंसू बहा रहे हैं। क्योंकि मंडियों में उन्हें अपनी उपज की उचित कीमत नहीं मिल रही है। किसानों की मानें तो मटर की फसल में प्रति एकड़ 30 से 35 हजार रुपए की लागत आती है, लेकिन मंडियों में यह महज 15 से 20 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से बिक रहा है इसलिए किसानों को लागत भी पूरी नहीं मिल पा रही है। आलम यह है कि किसान की मेहनत को व्यापारी रद्दी के भाव खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।

रात को जमकर बवाल

इस बार किसानों का गुस्सा फूट रहा है। तीन दिन पहले मटर किसानों ने कृषि उपज मंडी में आधी रात को जमकर बवाल काटा। मटर की उपज लेकर मंडी पहुंचे किसानों को जब व्यापारियों ने उचित दाम नहीं दिया तो जिले के हजारों किसानों ने अपने ट्रैक्टर और अन्य वाहन कृषि उपज मंडी के मार्ग पर खड़े कर सड़क जाम कर दी। इस दौरान मंडी आने जाने वाले व्यापारियों के ट्रक भी जाम में फंस गए। किसानों ने कई ट्रकों की हवा भी निकाल दी।

आंदोलन छेड़ दिया था

कृषि उपज मंडी में मटर की उपज लेकर बेचने पहुंचे किसानों को व्यापारियों ने 15 और 20 प्रति बोरा के हिसाब से मटर खरीदने के रेट दिए, जिससे किसान आक्रोशित हो गए और उन्होंने सड़क जाम कर आंदोलन छेड़ दिया था। शाम करीब 6: 00 बजे से शुरू हुआ आंदोलन रात 1:00 बजे तक जारी रहा। मंडी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे लेकिन किसान नहीं मानें। रात 2:00 बजे तक किसानों ने मंडी में जाम लगा कर रखा।

व्यापारी नहीं दे रहे सही दाम

डीके गेट पर भी किसानों ने अपनी ट्रैक्टर और अन्य वाहन लगा दिए थे। मंडी के गेट बंद कर दिए। किसानों का कहना है कि मटर की फसल उगाने में उन्हें प्रति एकड़ 30 से 40 हजार रुपए लागत आती है, लेकिन व्यापारी उसे इतनी कम कीमत में खरीदना चाहते हैं जिससे उनकी लागत तो छोड़ो मजदूरी भी नहीं निकलेगी। इस बार बारिश के कारण मटर की क्वालिटी काफी प्रभावित हुई है, एक ओर किसान अपनी उपज की उचित दाम निर्धारित करवाना चाह रहे हैं वहीं व्यापारी और प्रशासन क्वालिटी को लेकर दाम निर्धारित नहीं कर पा रहा है यानी मौसम के कारण दोनों पक्ष परेशान हैं।

फायदेमंद मटर का हजारों साल पुराना इतिहास

सब्जियों में मटर का दाना साइज में सबसे छोटा माना जाता है, लेकिन इसके आकार पर मत जाइए. इसमें गुणों का जो मेल-जोल है, वह बहुत कम सब्जियों में मिलता है। पाषाण युग में पैदा हुई मटर की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि वह मनुष्य के 'दिल को संभालकर' रखती है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है, लेकिन वसा बहुत कम पाई जाती है, इसलिए यह शरीर को जवान बनाए रखती है। छोटी सी इस मटर का इतिहास बड़ा ही रोचक माना जाता है। इस बात में कोई दो-राय नहीं है कि मटर की उत्पत्ति बहुत ही प्राचीन काल से है. यानी पृथ्वी पर यह हजारों साल से खाई जा रही है, लेकिन इस बात को लेकर कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि इसे सबसे पहले दुनिया के किस भाग में उगाया गया, क्योंकि कई रिसर्च रिपोर्ट इसका उत्पत्ति केंद्र अलग-अलग स्थानों पर बता रही हैं। 'वेजिटेबल' पुस्तक के लेखक व भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बिश्वजीत चौधरी का दावा है कि मटर की उत्पत्ति पाषाण युग में ही हो चुकी थी और इथोपिया इसका मूल केंद्र है। एक अन्य रिपोर्ट भी यह मानती है कि यह प्राचीन काल की उपज है और इसका उत्पत्ति केंद्र संभवतः दक्षिण-पश्चिमी एशिया, उत्तरीय पश्चिमी भारत, पूर्व सोवियत रूस के निकटवर्ती क्षेत्र और अफगानिस्तान माने जाते हैं।

30 एकड़ जमीन की गई चिन्हित

पाटन-कटंगी बाइपास से होगा मटर का कारोबार

इधर, देश-दुनिया में अपनी बेहतरीन क्वालिटी और स्वाद के लिए मशहूर जबलपुर के हरे मटर की होलसेल ट्रेडिंग के लिए कारोबारियों और मटर उत्पादक किसानों को सुविधा प्रदान करने के उदेश्य से नगर के पास ही स्थानीय प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए करीब 25 से 30 एकड़ जगह चिन्हित की है, जहां से आने वाले दिनों में सिर्फ मटर की ट्रेडिंग होगी और शहर में जाम की स्थिति से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। काफी समय से मटर की ट्रेडिंग के लिए अलग से जमीन की मांग की जाती रही है। साल के पांच महीने होने वाले इस कारोबार को अच्छी जगह भी मिल जाएगी।

मंदिर के नजदीक जमीन देखी

जिला कलेक्टर की पहल के बाद प्रशासन के आला अधिकारियों के एक दल ने पनागर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुशील तिवारी के साथ पाटन और कटंगी बाइपास में मंदिर के नजदीक जमीन देखी है। शासन के आधिपत्य वाली 25 से 30 एकड़ यह जमीन अभी सिलिंग की है। इस दौरान कृषि उपज मंडी में मटर की ट्रेडिंग करने वाले कारोबारी भी साथ थे। इनका नेतृत्व जबलपुर कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष अजीत साहू कर रहे थे। साथ ही किसान संघ के कुछ पदाधिकारियों के साथ अधिकारियों ने जमीन चिन्हित करते हुए अपनी आगे की रणनीति पर जोर दिया।

मटर कारोबार को मिलेगी नई दिशा

सिर्फ मटर के लिए शासन की ओर से करीब 30 एकड़ जमीन को यदि सभी की सहमति के बाद हरीझंडी मिल जाती है तो मटर कारोबार को एक नई दिशा मिलने के साथ ही साथ अभी जहां 170 से 180 ट्रक देशभर में मटर की खेप लेकर जाते हैं, उनकी संख्या में भी इजाफा होगा और यातायात और पार्किंग की समस्या का भी हल निकल जाएगा। हालांकि मटर कारोबारियों ने जमीन को लेकर अभी अपनी मंशा जाहिर नहीं की है।

भारतीय सोयाबीन अनुसन्धान संस्थान, इंदौर की नई किस्मों को अधिसूचना का इंतजार

अगले साल तक किसानों को मिलेगी सोयाबीन की तीन नई किस्म

इंदौर। जागत गांव हमार

भारतीय सोयाबीन अनुसन्धान संस्थान, इंदौर किसानों के लिए सोयाबीन की रोगमुक्त और अधिक उत्पादन देने वाली अच्छी किस्मों को पेश करने के लिए निरंतर अनुसंधान करता रहता है। इसी कड़ी में भारतीय सोयाबीन अनुसन्धान संस्थान, इंदौर की माह मई 2023 के दौरान सोयाबीन की तीन नवीनतम किस्मों एनआरसी 181,188 और 165 की पहचान की गई है। लेकिन अभी इनकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद सम्भवत: अगले वर्ष किसानों को यह किस्म उपलब्ध हो जाएगी। गत दिनों भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर का 37 वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान संस्थान के निदेशक डॉ. केएच सिंह ने को बताया कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर की माह मई 2023 के दौरान सोयाबीन की कम समयावधि वाली तीन नवीनतम किस्मों एनआरसी 181,188 और 165 की पहचान की गई, लेकिन अभी इन किस्मों की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी सोयाबीन की यह तीन नई किस्में किसानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। संभावना है कि किसानों को यह नई किस्में अगले वर्ष तक उपलब्ध हो जाएंगी।

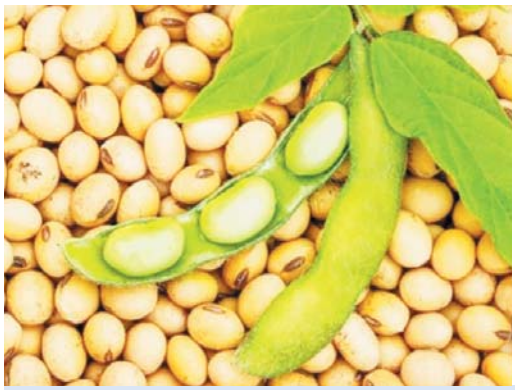

पहचानी गई तीन नई किस्मों की विशेषताएं

एनआरसी 181 - किस्म सीमित वृद्धि वाली है। जिसके सफेद फूल, गहरी भूरी नाभिका, भूरे रोयें होते हैं। कुनिट्ज ट्रिप्सिन इनहिबीटर मुक्त, पीला मोजैक एवं टारगेट लीफ ऑफ स्पॉट के लिए प्रतिरोधी यह किस्म रायजोक्टोनिया एरियल ब्लाईट, चारकोल सड़न एवं एन्थ्रेक्नोस के प्रति संवेदनशील है। मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित इस किस्म की परिपक्वता अवधि 93 दिन है और इसका औसत उत्पादन 16 -17 क्विंटल / हेक्टर है।

एनआरसी 188 - यह किस्म भी सीमित वृद्धि वाली है, लेकिन इसके फूल बैंगनी होते हैं। कली नाभिका, इसकी रोएं रहित हरी चिकनी फलियां होती हैं, जिन्हें मटर की फलियों की तरह खाया जा सकता है। मध्य क्षेत्र के लिए प्रस्तावित यह पहली वेजिटेबल टाईप किस्म है। इसकी परिपक्वता अवधि 77 दिन और इसका औसत उत्पादन 46.72 क्विंटल /हेक्टर हरी फलियां हैं।

एनआरसी 165 - यह किस्म भी सीमित वृद्धि वाली होकर इसके फूल बैंगनी होते हैं। इसकी भूरी नाभिका, रोयें रहित चिकनी फलियां, टारगेट ऑफ लीफ स्पॉट एवं अल्टरनेरिया लीफ ऑफ स्पॉट आदि बीमारियों के लिए प्रतिरोधी है। इसके अलावा तना मक्खी, चक्र भृंग तथा पत्ती भक्षकों के लिए भी प्रतिरोधी है। मध्य क्षेत्र में समय से बोवनी के लिए प्रस्तावित एक जल्दी पकने वाली किस्म है। जिसकी परिपक्वता अवधि 90 दिन और औसत उत्पादन 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

दूसरी प्रमुख फसल चने की बोनी अब तक 21.50 लाख हेक्टेयर में हो गई

प्रदेश में रबी फसलों की 121 लाख हेक्टेयर में बोवनी, 86 फीसदी पूरी

भोपाल। जागत गांव हमार

चालू रबी सीजन में गत वर्ष की तुलना में बोवनी में तेजी आई है। अब तक लगभग 121 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई है। जबकि गत वर्ष इस अवधि में 119 लाख 15 हजार हेक्टेयर में बोवनी हुई थी। इस प्रकार लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 86 फीसदी बोवनी पूरी हो गई है। वहीं राज्य की प्रमुख फसल गेहूं की बोनी 73.76 लाख हेक्टेयर में हो गई है। जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 81 फीसदी है। राज्य में मसूर की बोवनी लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में कर ली गई है।

कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 133 लाख 82 हजार हेक्टेयर है। इस वर्ष 140.26 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें ली जाएंगी। कृषि विभाग के मुताबिक अब तक 120.96 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। इसमें राज्य की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोवनी 73.76 लाख हेक्टेयर में हुई है। जबकि गत वर्ष अब तक 74.18 लाख हे. में गेहूं बोया गया था। इस वर्ष राज्य में 90.71 लाख हेक्टेयर गेहूं बोने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी प्रमुख फसल चने की बोनी अब तक 21.50 लाख हेक्टेयर में हो गई है जो गत वर्ष समान अवधि में 19.96 लाख हेक्टेयर में हुई थी। अन्य फसलों में अब तक मटर 2.62 लाख हे. में, मसूर 7.33 लाख हे. में बोवनी की गई है, जबकि मसूर का लक्ष्य 7.08 हेक्टेयर रखा गया है। इस प्रकार मसूर की बोनी शत-प्रतिशत हो गई है। राज्य में तिलहनों की बोवनी में कमी आई है। अब तक प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बोवनी 13.42 लाख हे. में हुई है। गत वर्ष अब तक 13.62 लाख हेक्टेयर में हुई थी। इस वर्ष 14.06 लाख हे. लक्ष्य रखा गया है। वहीं अलसी की बोवनी 1.19 लाख हे. में हुई है। इस वर्ष गन्ना 1.42 लाख हेक्टेयर में लिया जाएगा, अब तक 67 हजार हेक्टेयर में बोवनी हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल अनाज फसलें 74.23 लाख हेक्टेयर में, दलहनी फसलें 31.45 लाख हे. में एवं तिलहनी फसलें 14.61 लाख हेक्टेयर में बोवनी की गई हैं।

प्रदेश में रबी फसलों की बुवाई

7 दिसम्बर 2023 तक (लाख हे. में)

फसल	लक्ष्य	बोवनी
गेहूं	90.71	73.76
जौ	0.49	0.48
चना	22.35	21.50
मटर	2.75	2.62
मसूर	7.08	7.33
सरसों	14.06	13.42
अलसी	1.40	1.19
गन्ना	1.42	0.67

प्रदेश में रबी फसलों की बुवाई 121 लाख हेक्टेयर में

साईकिल व्हील से गेंहू की निराई गुड़ाई किसानों के लिए फायदेमंद

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. एसके जाटव, डॉ. आईडी सिंह, जयपाल छिगारहा एवं हंसनाथ खान की उपस्थिति में कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में बोये गए गेंहूं की प्रदर्शन में अटल बिहारी वाजपेयी कृषि महाविद्यालय खुरई से ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत आए छात्रों को साईकिल व्हील हो द्वारा गेंहूं में निराई-गुड़ाई का प्रशिक्षण दिया गया।

किसान जो अपनी पूर्ण शक्ति व साधन फसल की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए लगाता है। ये अनैच्छिक पौधे इस उद्देश्य को पूरा नहीं होने देते। खरपतवार फसल के पोषक तत्व, नमी, प्रकाश, स्थान आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करके फसल की वृद्धि, उपज एवं गुणों में कमी कर देते हैं। खरपतवारों से हुई हानि किसी अन्य कारणों से जैसे कीड़े, मकोड़े, रोग, व्याधि आदि से भी नहीं ज्यादा होती है। इसी नुकसान को कम करने के लिए खरपतवार नियंत्रण एक अति आवश्यक हो जाता है। व्हील हो एक खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक यंत्र है। शुष्क भूमि निराई यंत्र, खूंटी प्रकार, मैन्युअल रूप से संचालित होता है, जो फसल पंक्तियों के बीच संचालन के लिए उपयुक्त है। इसमें एक फार होता है, और एक साईकिल का पहिया होता हैं जो हल्के लोहे की छड़ों से जुड़ी होती हैं। हैंडल की ऊंचाई को ऑपरेटर की आवश्यकता के अनुसार भी समायोजित किया जा सकता है। खरपतवार हटाने के लिए इसे फसल की कतारों के बीच चलाया जाता है। फार से मिटटी की जुताई होती है अर्थात मिटटी को चीरता हुआ जाता है जिससे नींदा मिटटी में दबकर नष्ट हो जाते है। पंक्तिबद्ध फसलों में निराई-गुड़ाई और अंतर-कृषि करने के लिए व्हील हैण्ड हो एक व्यापक रूप से स्वीकृत निराई-गुड़ाई उपकरण है। व्हील हो से निराई करने में समय एवं परिश्रम दोनों कम लगते है अर्थात कम समय एवं कम लगत में अधिक क्षेत्रफल की निराई की जा सकती है ।

कृषि वैज्ञानिकों ने बताया छत गृह वाटिका का महत्व और उपयोगिता

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

भारत के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सब्जी उत्पादन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। भूमि उपयोग, फसल विविधता, रोजगार के अवसर एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने सब्जी की अपनी एक अलग उपयोगिता है। सब्जियों से हमें खाद्य रेशा, खनिज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसाए, प्रोटीन जैसे आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। वर्तमान शोध परिणामों से यह भी पुष्टि होती है कि सब्जियों में पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के यौगिक जैसे बीटा कैरोटीनए, विटामिन सी, विटामिन ई तथा ग्लूकोसाइनोलेट इत्यादि हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं। अर्थात सब्जियों को रक्षात्मक भोजन भी कहा जाता है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार के मार्गदर्शन में केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा गृह वाटिका के रूप में सब्जियां छत पर उगाई जा रही हैं, जिसे टैरिस गार्डन कहा जाता है। खरीफ एवं रबी मौसम में गृह वाटिका के रूप में खेत में उगाई गई सब्जियां वर्षा के कारण बहुत प्रभावित होती हैं।

ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि व्यक्ति खरीफ एवं रबी मौसम में गृह वाटिका घर के पास खाली जमीन में नहीं लगायें। जहां अच्छी जल निकास की समुचित व्यवस्था है वहां गृह वाटिका सुचारू रूप से किया जा सकता है, परंतु जहां घर के आसपास भूमि एवं जल निकास की व्यवस्था नहीं है, वहां टैरिस गार्डन के रूप में परिवार के सदस्यों के लिए सब्जिया उगाई जा सकती हैं। घर में सीमेंट की खाली पड़ी बोरियों में छत पर पपीता लगाकर परिवार में कुपोषण की बीमारी को दूर किया जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. एसके सिंह, डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. यूएस धाकड़ए, डॉ. एसके जाटव एवं जयपाल छिगारहा द्वारा विगत 5 वर्षों से टैरिस गार्डन एवं गृह वाटिका की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में जिले के विभिन्न ग्रामों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही इससे अनेकों लाभ हैं जैसे-परिवार को उच्च गुणवत्ता का पोषण, घरेलू खर्चों में बचत, सब्जियां कार्बनिक रूप में उपयोग, विषैले कीट नाशी रसायनों से मुक्त, घर के बुजुर्ग एवं सेवानिवृत्त व्यक्तियों की भागीदारी आदि प्रमुख है।

किसानों की निराशा होगी दूर | पूसा और इफको करेंगे सहयोग

इफको के एमडी डॉ. यूएस अवस्थी ने उर्वरकों में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अपने विचार साझा किए

भारत में किसानों की खराब होती भूमि की सेहत सुधारेगी बिटिश की कंपनी

भोपाल। जागत गांव हमार

नाइट्रोजन और फास्फेटिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से भारत की खेती में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने लगी है। नतीजा यह है कि अधिकांश क्षेत्रों के उत्पादन में या तो ठहराव आ गया है या फिर इनकी कमी से पौधों में कई तरह के रोग लग रहे हैं। सल्फर, जिंक, बोरान, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसे पोषक तत्वों की कमी से जमीन बीमार हो गई है। पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर इनकी कमी होती है तो फसलों में कई तरह के रोग लग जाते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी पूरा करने के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है और निजी कंपनियां भी। कई निजी कंपनियां अलग-अलग पोषक तत्वों को बेच रही हैं। खेती की इस कमी को पूरा करने के लिए एंग्लो अमेरिकन नामक इंग्लैंड की एक कंपनी ने पॉली-4 नामके एक प्रोडक्ट की भारत में शुरुआत की है। इसके इस्तेमाल से एक साथ चार पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि यह प्रोडक्ट पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी में पोटैशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम चार तत्वों की कमी एक साथ पूरी होगी। इस कंपनी ने भारत में खराब हुई खेतों की मिट्टी की सेहत को ठीक करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान, पूसा और इफको के साथ हाथ मिलाया है। इफको इसकी मार्केटिंग करेगी। इसे किसानों तक पहुंचाने को लेकर ब्रिटिश कंपनी ने हाल ही में नास कॉम्प्लेक्स में पूसा के सहयोग से एक सम्मेलन आयोजित किया। जिसमें कई जाने-माने कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहे। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि मिट्टी की जांच में यदि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिख रही है तो उसे नजरंदाज न करें बल्कि उसकी पूर्ति करें।

रिसर्च को साथ काम करने की जरूरत

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. एके सिंह ने कहा कि आज कृषि क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उसका समाधान इंडस्ट्री और रिसर्च संस्थानों को मिलकर करने की जरूरत है। मिट्टी की सेहत, फसलों की उत्पादकता और मानव स्वास्थ्य से जुड़े जो मुद्दे हैं उनका समाधान करना होगा। इफको के एमडी डॉ. यूएस अवस्थी ने उर्वरकों में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अपने विचार साझा किए।

किन पोषक तत्वों की भारी कमी

दरअसल, इस समय भारत के खेतों में 39 फीसदी जिंक, 23 फीसदी बोरॉन और 42 फीसदी सल्फर की कमी है। ऐसे में पोषक तत्वों का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसीलिए सरकार ने सल्फर कोटेड यूरिया की शुरुआत कर दी है। जिंक और बोरोन कोटेड यूरिया भी लाने की तैयारी है। ताकिइन दोनों तत्वों की भी जमीन में पूर्ति की जा सके। इस बीच पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए निजी कंपनियां भी बाजार में आ रही हैं। जिस तरह से सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपेक्षा की गई है और अब उसके साइड इफेक्ट दिखाई देने लगे हैं उसे देखते हुए एक नया और बड़ा बाजार दिखाई पड़ रहा है। बस इस बारे में किसानों को जागरूक करने की जरूरत है।

खेती के क्षेत्र में उतरी खनन कंपनी

एंग्लो अमेरिकन एक वैश्विक खनन कंपनी है, जिसकी स्थापना 1917 में सर अर्नेस्ट द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। यह ब्रिटिश कंपनी है और इस समय दुनिया भर में इस कंपनी के 105760 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसका कुल रेवेन्यू 3512.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। अब यह फसल पोषण के क्षेत्र में उतर गई है और विश्व के कई देशों में कारोबार कर रही है। दावा है कि इसका उत्पाद मिट्टी को संरक्षित करते हुए किसानों को अधिक अन्न उगाने में मदद करता है। यह पैदावार, गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ा सकता है, क्योंकि यह बहु-पोषक और ऑर्गेनिक तत्व है। कंपनी ने दावा किया है कि 1500 से अधिक वैश्विक वाणिज्यिक प्रदर्शनों से पता चलता है कि पॉली-4 के इस्तेमाल से इसकी उपज में औसतन 3-5 फीसदी का सुधार हुआ है।

-सिर्फ सात दिन में हो जाएगा तैयार, तकनीक से मकान की छत पर या एक कमरे में भी उगाने से अच्छा मुनाफा

पशुपालक अब हाइड्रोपोनिक विधि से उगाएं हरा चारा

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

हाइड्रोपोनिक तकनीक कम समय और कम लागत में हरा चारा उत्पादन की बेहद कारगर विधि है। इसमें बिना मिट्टी और कम पानी में सात दिन के अन्दर हरा चारा उगाया जा सकता ह। इस तकनीक में ऐसे पोषक तत्वों को प्रयोग में लाया जाता है, जो जल में घुलनशील होते हैं. इसमे कैल्शियम, मैग्निशियम ,पोटैशियम, नाइट्रेट, सल्फेट और फॉस्फेट को पोषक तत्व के रूप में इस्तेमाल किया जाता ह। इससे हरा चारा के लिए गेहूं, बाजरा, और मक्का की फसल आसानी से उगाई जा सकती ह। अगर आप शहर में डेयरी पालन या डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं तो इस तकनीक से आप अपने मकान की छत पर या एक कमरे में भी 7 दिन के अन्दर हरा चारा उगा कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का उपयोग करके गर्मी या सूखे के दौरान अच्छी गुणवत्ता वाला हरा चारा उगाया जा सकता है। डेयरी उद्योग में चारा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस समय बाज़ार में हरे का दाम अधिक हैं। ऐसे में पशुपालन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का उपयोग करके चारे का उत्पादन कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक से चारा उत्पादन डेयरी व्यवसाय के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है।

चारा उत्पादन के लिए पॉलीहाउस

हाइड्रोपोनिक तकनीक के माध्यम से चारे के उत्पादन के लिए आश्रय स्थान की आवश्यकता होती है। इसके लिए मुख्य रूप से शेडनेट का उपयोग करना चाहिए। यदि 50 प्रतिशत शेड नेट या पॉलीहाउस का उपयोग किया जाए तो यह फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक सूर्य की रोशनी भी प्रदान करेगा। चारा उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए शेड नेट के बाहर आवश्यकतानुसार 200 से 500 लीटर का टैंक लगाना चाहिए और टैंक से पानी को एक पाइप के माध्यम से शेड नेट तक लाना चाहिए। हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन के लिए, सीधे बढ़ने वाली फसलों का चयन किया जाना चाहिए। हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन के लिए मुख्य रूप से मक्के की फसल का चयन करना चाहिए।

हाइड्रोपोनिक तकनीक

केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों में नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधें उगने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक में चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 80 से 85 प्रतिशत आर्द्रता में उगाया जाता है। सामान्यतया पेड़ -पौधे अपने आवश्यक पोषक तत्व जमीन से लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक तकनीक में पौधों के लिये आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करने के लिए पौधों में एक विशेष प्रकार का घोल डाला जाता है। इस घोल में पौधों के लिये आवश्यक खनिज एवं पोषक तत्व मिलाये जाते हैं। पानी, कंकड़ों या बालू में उगाये जाने वाले पौधों में इस घोल को महीने में एक-दो बार केवल कुछ मात्रा ही डाली जाती है। इस घोल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम , मैग्नीसियम, कैल्शियम , सल्फर, जिंक और आयरन आदि तत्वों को एक खास अनुपात में मिलाया जाता है, ताकि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहे।

फसलों के उत्पादन में होगी बढ़ोतरी और लागत भी कम

अब कम समय में किसान तैयार कर सकते हैं तीन जैविक खाद

भोपाल। जागत गांव हमार

इन दिनों भारत में जैविक खेती की खूब चर्चा है। कई किसान जैविक खेती कर रहे हैं और इसमें तेजी से सफलता भी पा रहे हैं। इस खेती में पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं यह खेती किसानों के लिए इतनी लाभदायक है कि वे इसे लंबे समय तक आसानी से कर सकते हैं। इसमें लागत कम आती है और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। इसलिए किसानों को इसमें फायदा होता है।

जैविक खेती को एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा है।सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई जागरुकता अभियान चला रही है। दरअसल खेती में रसायनों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खोती जा रही है। इससे साल दर साल फसलों का उत्पादन कम होता जा रहा है। ऐसी ही समस्याओं को देखते हुए किसान तेजी से जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। इसमें जैविक खाद भी पूरी मदद करते हैं। आप चाहें तो बेहद कम समय में ये तीन जैविक खाद कम खर्चे में बना सकते हैं।

वर्मी कंपोस्ट खाद

वर्मी कंपोस्ट एक उत्तम जैव उर्वरक है। इसे केंचुआ खाद भी कहा जाता है। यह खाद केंचुआ और गोबर की मदद से बनाई जाती है। इसे तैयार होने में लगभग डेढ़ महीने लगते हैं। यह खाद वातावरण को प्रदूषित नहीं होने देती है। इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो फसलों को तेजी से विकास में मदद करता है और मिट्टी को बेकार नहीं होने देता है।

कंपोस्ट खाद

आमतौर पर कंपोस्ट खाद को कूड़ा खाद भी कहा जाता है, क्योंकि यह घर के कूड़े, पौधों के अवशेषों, कूड़ा कचरा, पशुओं के मलमूत्र, पशुओं के गोबर, खेतों का घास-फूस या खरपतवार आदि को विशेष परिस्थियों में सड़ने गलने से खाद बनती है। कंपोस्ट खाद की खासियत ये होती है कि ये गंध रहित होती है।

हरी खाद

बिना सड़ा हुआ पौधों का वह भाग जिसे हम मिट्टी में मिलाकर खाद के रूप में उपयोग करते हैं, उसे हरी खाद कहते हैं। हरी खाद जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मकसद नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करना और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ यानी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है ताकि कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए।

जैविक खेती के कई फायदे

जैविक खेती करने के कई फायदे हैं। जैविक खेती करने से जहां फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। वहीं इसकी खेती करने वाले किसानों को कम लागत में अच्छा मुनाफा भी होता है। इसकी खेती में जैविक खाद का प्रयोग होने से यह स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। वहीं यह पर्यावरण के लिए भी काफी बेहतर होता है। जैविक खेती के लिए पानी का भी कम इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जैविक खेती से पशुपालन को भी बढ़ावा मिलता है। जैविक खेती और पशुपालन आपस में जुड़े हुए हैं। जहां खेतों में प्रयोग होने वाली जैविक खाद में पशुओं का गोबर और मूत्र होता है, तो वहीं पशुओं के आहार के रूप में खेतों से तैयार किया हुआ हरा चारा मिल जाता है।

खाद के छिड़काव के लिए सबसे उपयोगी

किसानों को सब्सिडी पर सरकार दे रही ड्रोन

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों को फसल की बुआई से लेकर कटाई तक काफी समय लग जाता है। जिसके कारण किसानों को कोई अन्य कार्य करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। जिसके कारण किसान एक समय में एक ही फसल उगा पाते हैं। ऐसे में किसान नई तकनीकों का इस्तेमाल कर घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। कृषि तकनीकों की बात करें तो आज के समय में ड्रोन का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। फसलों में उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं किसानों को इसके लिए सरकार से सब्सिडी भी मिलती है।

ड्रोन के जरिए छिड़काव पर जोर- बिहार सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत रबी की खेती में ड्रोन के जरिए कीटनाशकों के छिड़काव पर जोर दिया जा रहा है। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें सरकार किसानों को प्रति एकड़ 250 रुपये का अनुदान देगी। एक किसान अधिकतम 10 एकड़ तक ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों का छिड़काव करने पर सरकार से सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। किसान आलू, मक्का और गेहूं के साथ तिलहन, दलहन पर कीटनाशकों का छिड़काव करा सकते हैं।

ड्रोन के उपयोग के लाभ

आंकड़ों के मुताबिक हर साल 35 फीसदी फसल कीट, खरपतवार और बैक्टीरिया के कारण बर्बाद हो जाती है। जिस वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसान पारंपरिक तरीके से कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। जिस वजह से किसानों के ऊपर कीटनाशक का बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि ड्रोन से छिड़काव करने से पानी, श्रम और पूंजी की बर्बादी नहीं होगी। ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव करने से किसानों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

किसानों को सब्सिडी

गौरतलब है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चौथे कृषि रोड मैप के तहत 2023-24 के लिए जिले में कृषि कार्य के लिए मानव रहित ड्रोन का उपयोग करने की मंजूरी पौधा संरक्षण विभाग को मिली है। गया जिले में रबी फसल में पहली बार जिले के किसान सरकार द्वारा अनुदानित दर पर ड्रोन के माध्यम से खेतों में लगी फसलों में जैविक और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव कर सकेंगे।

किसानों को दी जाएगी ड्रोन की ट्रेनिंग

आवेदन मिलने के बाद विभाग स्थल निरीक्षण करेगा और ड्रोन उपलब्ध कराकर विशेषज्ञों के माध्यम से छिड़काव कराया जाएगा। कोई भी किसान अपने खेत में लगी आम, लीची और बागवानी फसलों में बीमारियों से बचाव के लिए ड्रोन छिड़काव का लाभ उठा सकता है। इससे किसानों को कम खर्च के साथ-साथ खाद की बचत और फसल में उर्वरकों और कीटनाशकों का एक समान छिड़काव करने से बेहतर उत्पादन मिलेगा। छिड़काव शुल्क का 50 प्रतिशत अधिकतम 250 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देय होगा। जिसमें अधिकतम 10 एकड़ के लिए प्रति किसान 2500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को छिड़काव के लिए उर्वरक और कीटनाशक स्वयं उपलब्ध कराने होंगे।

मांग अनुसार श्रेणी के यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया निर्धारित

भोपाल। कृषि अभियांत्रिकी , संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा मांग अनुसार श्रेणी के यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की है। ई - कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से नवीन तकनीक के चिन्हित उन्नत कृषि यंत्रों पर (मांग अनुसार (आन डिमांड) श्रेणी अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। इस के लिए उन्नत कृषि यंत्र चिन्हित किए गए हैं। इन यंत्रों के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी आवेदन सामान्य प्रक्रिया अनुसार - मांग अनुसार श्रेणी के यंत्रों के लिए भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही किए जाएंगे। इन यंत्रों के लिए पृथक से लक्ष्य जारी नहीं किए जाएंगे। इस श्रेणी अंतर्गत चिन्हित यंत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों के लिए लाटरी नहीं की जाएगी। उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित होने पर कृषक का आवेदन पोर्टल पर चयनित कृषकों की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा। अनुमोदन की सूचना कृषक को एसएमएस के माध्यम से दी श्रेणी अंतर्गत अनुमोदित आवेदनों में डीलर चयन तथा आगे की समस्त प्रक्रियाएं, समयावधि, लाटरी बाद चयनित कृषकों की प्रक्रिया के सामान ही रहेगी।

मांग अनुसार श्रेणी में शामिल कृषि यंत्र

वर्तमान में जिन कृषि यंत्रों को मांग अनुसार श्रेणी में रखा गया है, वे हैं - पैडी राइस ट्रांसप्लांटर, पावर हैरो , हैप्पी सीडर / सुपर सीडर ,न्यूमेंटिक प्लांटर, हे रेक / स्ट्रॉ रेक,बेलर हाइड्रोलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर (ट्रैक्टर चलित), ब्रॉड बेड फरो - प्लांटर, किसान ड्रोन, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, ऑइल एक्सट्रेक्टर, मिलेट मिल, मिलेट प्रसंस्करण प्लांट (मिलेट मिल, क्लीनर कम ग्रेडर एलीवेटर सहित, डी स्टोनर)। पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र (धरोहर राशि रु.1000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अनिवार्य होगा)।इच्छुक कृषक शेष यंत्रों के लिए निर्धारित धरोहर राशि रु.5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर इस श्रेणी अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)